समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

ट्रंप प्रशासन के दबाव मे Apple ने हटाए ICE ट्रैकिंग ऐप्स, उठे निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल

Sanket Morankar
Published on 03 Oct 2025

टेक्नोलॉजी दिग्गज **Apple** ने अमेरिका में **इमिग्रेशन और कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE)** अधिकारियों की गतिविधियों को ट्रैक करने वाले ऐप्स को अपने ऐप स्टोर से **हटा दिया है**। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति **डोनाल्ड ट्रंप** के प्रशासन से मिली शिकायतों के बाद लिया गया।

Apple ने **गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025** को घोषणा की कि उसने लोकप्रिय ऐप **ICEBlock** समेत कई अन्य समान ऐप्स को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। यह ऐप्स उपयोगकर्ताओं को ICE अधिकारियों की उपस्थिति के बारे में **सतर्क** करते थे।

ICEBlock एक क्राउडसोर्सिंग ऐप था जिसे अमेरिका के कुछ इलाकों में अप्रवासी समुदायों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता एक-दूसरे को सूचना देते थे कि किस इलाके में **ICE अधिकारी मौजूद है या रेड कर रहे है**।

- यह डेटा सीमित समय तक ही उपलब्ध रहता था।
- ऐप **कोई निजी जानकारी स्टोर नहीं करता था**।
- इसका उद्देश्य समुदायों को **सतर्क करना और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना** था।

ट्रंप प्रशासन की ओर से Apple को सूचित किया गया कि ऐसे ऐप्स **कानून व्यवस्था मे बांधा** डालते हैं और **अवैध अप्रवासियों** को छिपने में मदद करते हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, *“[illegible]”*

इसके बाद Apple ने इन ऐप्स की **नीतियों और नियमों की समीक्षा** की और उन्हें प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्णय लिया।

ICEBlock के डेवलपर्स ने Apple के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह **डिजिटल सेसंरशिप** का एक स्पष्ट उदाहरण है।

डेवलपर्स ने कहा,
"[illegible]"

डिजिटल अधिकार संगठनों जैसे **Electronic Frontier Foundation (EFF)** और **Fight for the Future** ने भी Apple के इस फैसले की निंदा की और इसे **राजनीतिक दबाव मे लिया गया फैसला** बताया।

Apple पहले भी कई बार इस तरह के निर्णय ले चुका है।

- **हांगकांग** में Apple ने एक ऐप हटाया था जो प्रदर्शनकारियों को पुलिस की मूवमेंट की जानकारी देता था।
- **रूस और चीन** में भी सरकार के दबाव में ऐप्स हटाए जा चुके हैं।

इन मामलों में हर बार **तकनीकी स्वतंत्रता बनाम सरकारी हस्तक्षेप** की बहस तेज़ हो जाती है।

तकनीकी और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकारें ऐसे ऐप्स को बंद कराने में सफल होती रहीं, तो भविष्य में **फ्री स्पीच, सोशल जस्टिस, और डिजिटल प्रोटेक्शन** के क्षेत्र में कार्यरत कई प्लेटफॉर्म को बंद किया जा सकता है।

प्रसिद्ध साइबर लॉ एक्सपर्ट **राजीव रंजन** कहते हैं:
"[illegible]"

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान **अप्रवासियों के खिलाफ कड़े कानून** और **ICE की कार्रवाई** काफी बढ़ी है।
इस प्रकार के ऐप्स उनके एजेंडे में **रुकावट** माने जा रहे हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि Apple पर दबाव बनाकर ट्रंप प्रशासन ने अप्रवासी समुदायों की **संरक्षा तंत्र को कमजोर** करने की कोशिश की है।

Apple द्वारा ICE ट्रैकिंग ऐप्स को हटाने का फैसला केवल एक तकनीकी अपडेट नहीं है, बल्कि यह एक **वैचारिक संघर्ष** की ओर इशारा करता है।
यह संघर्ष है — **टेक कंपनियों की जवाबदेही**, **राजनीतिक दबाव**, और **नागरिक अधिकारों** के बीच।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.